जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 30 संख्याः 77 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 17 जनवरी, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को अपनी राजनीतिक यात्रा का आगाज परबतसर (नागौर) से किया। परबतसर में किसान सम्मेलन के जरिये पायलट ने न केवल अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि पेपर लीक प्रकरण में अपनी ही सरकार को जोरदार तरीके से घेरा भी। पायलट ने राजस्थान में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर कहा, जब भी खबर पढ़ता हूँ....''पेपर लीक हो गये, कभी भर्ती तो कभी परीक्षा कैंसिल हो गई...यह सब सुनकर मन बहुत आहत होता है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को छोटे-मोटे दलालों के बजाय बड़े एवं प्रमुख सरगनाओं को पकड़ना चाहिये।'' पायलट ने किसानों की मांगों का भी जोरदार समर्थन किया, उन्होंने कहा कि, केन्द्र सरकार के समक्ष किसान आंदोलन के समय किसानों ने जो मांगें की थी उन्हें तत्काल पूरा किया जाये।

मु.मंत्री के लिये किसानों का मांग पत्र तैयार करना शुरु किया पायलट ने

नागौर में आयोजित विशाल रैली में उन्होंने जनता की मांग पर स्वीकृति प्राप्त की कि, एम.एस.पी.के लिये कानून बनाया जाये

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। सचिन पायलट ने किसानों की विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।

उन्होंने नागौर में अपनी विशाल जनसम्पर्क रैली में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लाने हेतु कानून बनाने की मांग की। सभा में मौजूद किसानों, व स्त्री-पुरुषों ने पायलट की मांग का जोरदार समर्थन किया।

वे 20 जनवरी तक सभाएं जारी रखेंगे। अभियान का समापन जयपुर में होगा जहां एक विशाल जनसभा में वे मुख्यमंत्री को किसानों के कल्याण की मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। गहलोत बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में है पर सचिन पायलट की सभा में आ रही भारी भीड़ से उनके पसीने छूट रहे हैं, जो कि सचिन

- बीस तारीख तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान में मुख्यतया जाट बाहुल्य क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी रैलियां आयोजित करेंगे पायलट।
- नागौर में जनता से पारित कराई दूसरी बड़ी मांग थी, पेपर लीक मामले में मुख्य बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ा जाये, न कि, छोटे-मोटे दलालों को ही।
- गहलोत मंत्रिमण्डल के सदस्य हेमाराम चौधरी ने भी नागौर रैली में मांग की कि, नये युवा नेताओं को पार्टी में, राजनीति में उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये, जो फिलहाल नहीं होता दिख रहा।
- पायलट के करीबी नेता ने भी मांग की कि, समाज के विभिन्न वर्गों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पार्टी 21 सीटों पर न सिमट जाये, जैसा कि गहलोत की दूसरी पारी के बाद हुआ था, तथा पायलट कांग्रेसाध्यक्ष के रूप में पुनः पार्टी को सत्ता में लाने में सफल हुए थे।

को देखने व सुनने आ रही है। खासकर युवा तो सचिन के प्रति मंत्रमुग्ध से हैं।

इसके साथ सचिन पायलट ने सरकार पर और मुख्यमंत्री पर टीचर्स भर्ती में सामान्य ज्ञान पेपर लीक के लिए भी कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा, कभी पेपर लीक हो जाता है कभी परीक्षा रद्द हो जाती है यह बहुत दर्दनाक व तनाव परक है। पढ़ाई के लिए बच्चे और उनके माता पिता कितना कष्ट सहते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चे रात-दिन पढ़ाई करते हैं।

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को चाहिए कि पेपर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''अमर्त्य सेन की, भारत से वाकफियत बहुत पुरानी व सतही है''

उन्होंने अचानक निद्रा से जागते हुए वक्तव्य दिया कि, ममता बनर्जी देश की प्र.मंत्री बनने के लिये सबसे उपयुक्त है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। बहुत पहले भारत छोड़ चुके एक भारतीय अमर्त्य सेन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के चयन को लेकर की गई टिप्पणी ने लोगो को हसंने और मंनोरजन करने का मौका दे दिया।

अमर्त्य सेन ऐसा महसूस करते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में भारत का प्रधानमंत्री बनने की विशिष्ट योग्यता है। बिना सोचे-समझे किए गए इस आकलन ने पलटवार की टिप्पणियों के एक बवंडर को जन्म दे दिया है।

ममता बनर्जी ने भी तुरन्त प्रभाव से प्रतिक्रिया दी कि ''अमर्त्य सेन जी द्वारा कही गई बात एक आदेश के समान है'' ऐसा जैसे कि यह आदेश उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के योग्य बनाता हो और इससे उनके पक्ष में पूरे देश के वोट पड़ जाए।

अमर्त्य सेन ने इतना समय पहले भारत छोड़ था कि उस समय को प्राचीन काल ही कहा जा सकता है। फिर भी ऐसे मकान मालिकों, जो किराए पर दिए हुए अपने मकानों को यदा-कदा देखने जाते रहते हैं, की तरह अमर्त्य सेन भारत के लिए सही मार्ग चुनने वाले व्यक्ति के रूप

- अर्मत्य सेन उस जमाने के व्यक्ति हैं, ''जो सदा से मानते आये हैं कि, बंगाल ही भारत है, और भारत बंगाल।''
- वे भूल गये कि, लगातार प्रयास के बावजूद, ममता बनर्जी की पार्टी एक विधायक नहीं बना पायी बंगाल से बाहर त्रिपुरा, गोवा में उनका प्रयास इतना विफल हुआ कि, उनके उम्मीदवार चुनाव ही नहीं हारे, बल्कि जमानत भी खो बैठे।
- अर्मत्य सेन इस तथ्य से भी वाकिफ नहीं लगते कि, ममता जी की पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार काण्डों में लिप्त पाये जा रहे हैं और इस बारे में ममता जी कभी-कबार कुछ भाषण देने के अलावा कुछ नहीं कर पाई हैं। अर्मत्य सेन का पुराना प्रतिपादित सिद्धांत था, भ्रष्टाचार, समाज की नैसर्गिक कार्यकुशलता में घुन लगा देता है।
- साथ ही, नये परिदृश्य में कई नये नेता जैसे केजरीवाल, चन्द्रशेखर राव राष्ट्रीय नेता बनने के लिए अधिक सशक्त दावेदार हैं, तथा ममता जी की पार्टी अभी तक प्रदेश स्तर की पार्टी की मान्यता ही प्राप्त कर पाई है चुनाव आयोग से।

में अब भी एक स्वामित्व अधिकार चाहते हैं सेन स्पष्ट रूप से भारत की वर्तमान वास्तविकताओं से वाकिफ नहीं हैं।

सेन इन छोटे तथ्यों पर गौर नहीं कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल के बाहर एक भी सीट जीतने में विफल रही हैं। अमर्त्य सेन के लिए भारत बंगाल है और बंगाल ही भारत है। अत: बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता में वह योग्यता है कि वह भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है, बावजूद इसके कि अपने राज्य के बाहर उन्हें गिने-चुने वोट ही मिल सकते हैं।

अमर्त्य सेन की बकवास पर गंभीर राजनेताओं की तरफ से शायद ही कोई प्रतिक्रिया आई होगी, लेकिन प्रतिद्वंन्द्वी पार्टियों की तरफ से इसे लेकर विरोध और प्रशंसात्मक टिप्पणियां तुरंत आने लगी।

ममता बनर्जी बार-बार हाथ लगी विफलताओं और अपने राज्य के बाहर कोई उपस्थिति दर्ज ना करा सकने के कारण राजनीतिक रूप से विलुप्त हो गई हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता अब तक प्राप्त नहीं हुई तथा उनकी पार्टी विशुद्ध रूप से एक राज्य स्तरीय पार्टी है।

ममता का कभी एक नैशनल लैवल के नेता का थोड़ा बहुत कद था, लेकिन नए उभरे नेताओं के आगे बाद में उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। आम आदमी पार्टी (आप) के केजरीवाल का कद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री का रोड शो

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पार्लियामैंट स्ट्रीट पर 200 मीटर लम्बा रोड शो निकाला। पटेल चौक से एन.डी.एम.सी. कॉन्वैंशन सैंटर तक चले रोड शो के जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सम्मान किया गया।

एक दर्जन से ज्यादा राज्यों के पारम्परिक लोक गायकों व नर्तकों ने

- नई दिल्ली में पार्लियामैंट स्ट्रीट पर भाजपा ने प्रधानमंत्री का 200 मीटर लम्बा रोड शो किया। इसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक शुरु हुई।

रोड शो में हिस्सा लिया। इसके बाद कॉन्वैंशन सैंटर पर भाजपा का दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक शुरु हुई। इसमें दस राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के कार्यकाल का अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव तक विस्तार किया जाएगा। उन राज्यों जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने है उनके लिए रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने रविवार को एक बैठक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं पर फोकस किया कर्नाटक में

''गृह लक्ष्मी स्कीम'' के अन्तर्गत हर महिला के खाते में प्रति माह दो हजार रूपये जमा करने का वादा किया

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए तुफानी प्रचार करने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कर्नाटक पहुंची और उन्होंने महिलाओं की एक लक्षित कल्याणकारी योजना को लेकर कांग्रेस का प्रचार किया। उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2 हजार रूपए किए जाएंगे।

बैंग्लोर में आयोजित एक रैली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सशक्त करने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहरायी। कर्नाटक में महिलाएं एक अति महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियां लक्ष्य बना रही हैं। प्रियंका ने भी महिलाओं को लुभाते हुए इन्दिरा गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एल.पी.जी. की भारी कीमतों और मंहगे दैनिक खर्चो का भार उठाना होता है। ''गृह लक्ष्मी योजना इसी भार को साझा करने का एक प्रयास है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि 24 हजार रूपए सालाना राशि ''अनकंडीशनल यूनिवर्सल बेसिक इनकम'' के रूप में ''गृह लक्ष्मी योजना'' के तहत महिलाओं के खतों में सीधे जमा करायी जाएगी।

- दिनभर उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखकर कर्नाटक की भाजपा सरकार ने भी कई मनलुभावन महिला उन्मुख स्कीमों की घोषणा की, अखबारों व टी.वी. पर भारी विज्ञापन जारी करके
- जद (सैक्युलर) ने भी घोषणा की कि, अगर सत्ता में आयी तो एक महिला को उपमुख्यमंत्री जरूर बनायेगी।
- भाजपा सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप चिपक सा गया है, तथा पार्टी के लिये, दुर्भाग्यपूर्ण दिन था सोमवार, क्योंकि कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने भी एक टेप जारी किया, जिसमें वे यह साबित करना चाहते थे कि, चित्रदुर्ग के विधायक को 90 लाख रूपये की रिश्वत दी है। टेप में ठेकेदार व भाजपा विधायक के बीच इस संदर्भ हुए वार्तालाप को साफ सुना जा सकता है।

मजे की बात यह है कि भाजपा, जिसने मुफ्त बिजली के वायदे की आलोचना की थी, ने भी इसी ताल से ताल मिलाई और महिला मतदाताओं को रिझाने की मुहि में कांग्रेस को मात देने की कोशिश की। मंगलवार को जिस दिन प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए बैंगलोर आई थी उस दिन भाजपा ने महिला उन्मुखी योजनाओं की लिस्ट बनाई और जोर-शोर से टी.वी. व अखबारों में उसके विज्ञापन प्रसारित किए। जनतादल (एस) ने तो सत्ता में आने पर महिला उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया।

संयोगवश प्रियंका के लिए भारी भी आई बिल्कुल वैसेही जैसे गत वर्ष राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख डी.के. शिवकुमार तय पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता 40 प्रतिशत कमीशन की सरकार से थक चुकी है और उसे उखाड़ फेंकना चाहती है।

प्रियंका जिस दिन बैंगलोर आई उसी दिन कर्नाटक सरकार ने मीडिया में महिला सशक्तीकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 28 विज्ञापन प्रसारित करवाए। इअब राज्य में महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए रोचक जंग छिड़ गई हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने कहा कि, कांग्रेस वही वादे करती है जिन्हें पूरा कर सकती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया जहां चुनावों में पूरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया था जिसे नई सरकार ने लागू भी कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जापान सैन्य ताकत बनने की ओर अग्रसर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। चीन की बढ़ती ताकत और नॉथ कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण से जापान अपनी ''मिलिटरी पैसिफिज्म'' की नीति

- चीन की बढ़ती ताकत और नॉर्थ कोरिया द्वारा लगातार मिसाइल टैस्ट करने से चिंतित जापान ने ''मिलिटरी पैसिफिज्म'' की नीति त्यागने का फैसला किया है।

पर पुनर्विचार की ओर बढ़ रहा है। यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है।

शुक्रवार को वॉशिंगटन में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कीशीदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पारदर्शिता की आड़ में सरकार एक बार फिर जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका चाहती है

केन्द्रीय विधि मंत्री रिजीजू ने सुप्रीम कोर्ट के मु.न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांग की कि, कोलीजियम के सदस्यों में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 जनवरी। उच्चतर न्यायपालिका की न्यायिक नियुक्तियों में अपना दखल स्थापित करने की अनवरत् कोशिश के तहत केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) डी.वाय. चन्द्रचूड़ को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम, जो जजों की नियुक्ति करता है, में सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए।

कानून मंत्री ने एक पत्र में लिखा था कि इससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। इस मुद्दे पर गत वर्ष से सरकार व न्यायपालिका के बीच बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच ने

- विधि मंत्री ने आगे यह भी लिखा कि, इससे कोलीजियम के कामकाज में पारदर्शिता व जवाबदेही आयेगी।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, लगभग सात साल पहले, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बैंच ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि, मुख्य न्यायाधिश से सलाह मशविरा करके, कोलीजियम की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाये। पर, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट की इस राय पर, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और अब अचानक विधि मंत्री के खत के मार्फत सरकारी नुमाइन्दों को कोलीजियम का सदस्य बनाने की मांग की है।
- विधि मंत्री रिजीजू का इस लय में यह भी सुझाव है कि, हाई कोर्ट के कोलीजियम में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी होने चाहिये।
- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व आप ने, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया है, कोलीजियम प्रणाली को ''डायल्यूट'' करने के प्रयास की निन्दा की है।

सात साल पहले उसे कहा था कि कोलीजियम सिस्टम के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने हेतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर केन्द्र मैमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर (एम.ओ.जी.) पर चर्चा को अंतिम रुप दे पर तब केन्द्र ने इस पर आगे कदम नहीं बढ़ाया। अब रिजीजू का पत्र आया है जो पारदर्शिता के बहाने से की जा रही कोशिश है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल जूडिशियल अपॉइन्टमैंट कमीशन को रद्द करते हुए जो सुझाव दिया था, यह उसी का फॉलोअप है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कई अन्य की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने अपने न्यायपालिका पर पकड़ बनाने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)